



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 कार्तिक 1935 (श०)

(सं० पटना 822) पटना, वृहस्पतिवार, 24 अक्टूबर 2013

सं० 07 / विविध-३८ / 2012—1730
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

26 सितम्बर 2013

विषय:—पटना में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ₹ 10.97 करोड़ अनुदान के साथ स्वीकृत आधुनिक वधशाला (Abattoir) के जन-निजी भागीदारी अंतर्गत निर्माण पर राज्य सरकार की स्वीकृति।

बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित रही है। मवेशी पालन, बकरी पालन तथा पोल्ट्री इस अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। इस कारण राज्य में मवेशी, बकरों, भेड़ों और पोल्ट्री फार्म के मीट का बड़ा बाजार उपलब्ध है। लेकिन राज्य में मवेशियों के मीट प्रसंस्करण हेतु आधुनिक वधशाला (Abattoir) का पूर्णतः अभाव है। पटना जैसे बड़े शहरों में भी खुले में सड़कों पर मीट प्रसंस्करण व विक्रय का कार्य अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता रहा है। इस अस्वास्थ्यकारी व्यवस्था में सुधार हेतु आधुनिक वधशाला की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त आवश्यकता के मद्देनजर भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'वधशाला के आधुनिकीकरण की योजना' के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र के लिए वर्ष 2010 में ₹ 26.38 करोड़ के जन-निजी भागीदारी आधारित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) की स्वीकृति दी गई। इसमें भारत सरकार का अनुदान (ग्रांट) ₹ 10.97 करोड़ (दस करोड़ सन्तानवे लाख रु० मात्र) उपलब्ध है। शेष राशि निजी भागीदार को लगानी है। इसमें राज्य सरकार का कोई ग्रांट उपलब्ध नहीं है। पटना नगर निगम द्वारा परियोजना में 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी।

3. विगत वर्षों में परियोजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुड़को) को परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। नवंबर, 2012 में बुड़को द्वारा डेवलपर्स ने व्यालीफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई जिस दौरान देश के महत्वपूर्ण वधशाला डेवलपर्स ने परियोजना में रुचि दिखाई। परन्तु इन डेवलपर्स ने रामचक बैरिया में उपलब्ध 5 एकड़ भूमि का आकार काफी कम बताया। साथ ही, उक्त भूमि के निकट आवासीय अधिवास को भी परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। डेवलपर्स का ऐसा मानना है कि परियोजना में इंटीग्रेटेड व जीरो डिस्चार्ज सुविधा बनाने हेतु कम-से-कम 25–30 एकड़ भूमि शहर के बाहर होनी चाहिए। कई डेवलपर्स ने वार्ता के दौरान स्वयं भूमि क्रय करने में भी रुचि प्रदर्शित की है।

4. परियोजना की सफलता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बुड़कों द्वारा जन-निजी भागीदारी आधारित बिड डॉक्यूमेंट व कंसेसन एग्रीमेंट तैयार किया गया है। इन दस्तावेजों में निम्नलिखित मुख्य प्रावधान है :-

(क) निजी भागीदार स्वयं भूमि की व्यवस्था करेंगे और भूमि सहित पूरी परियोजना लागत में निवेश करेंगे। इसमें सरकार का निवेश उपलब्ध ग्रांट रु० 10.97 करोड़ के रूप में होगा। पटना नगर निगम परियोजना क्षेत्र में निजी भागीदार को आधुनिक वधशाला का कार्य करने हेतु लाइसेंस भी प्रदान करेगा।

(ख) परियोजना कंसेसन अवधि प्रथमतः 30 वर्ष के लिए होगी।

(ग) परियोजना अवधि में निजी भागीदार द्वारा 'वार्षिक लाइसेंस प्रीमियम' (Annual Licence Premium) का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष इस प्रीमियम में 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी।

(घ) जो बीडर सर्वाधिक वार्षिक लाइसेंस प्रीमियम की बोली लगाएगा उसे परियोजना अवार्ड किया जाएगा।

(ङ) परियोजना समाप्ति पर सभी परिसम्पत्ति सरकार/नगर निगम को हैंड ऑवर कर दी जाएगी। यदि सरकार चाहे तो लीज का पुनः नवीकरण भी शर्तों के अधीन कर सकेगी।

5. परियोजना की अन्य निम्नलिखित न्यूनतम तकनीकी विशेषताएं होंगी जिसे निजी भागीदार और बेहतर बना सकने को स्वतंत्र होगा:-

(क) परियोजना में दो स्लॉटर लाईन प्रस्तावित हैं— एक भैंस के लिए और एक बकरे के लिए।

(ख) वधशाला में पशुचिकित्सक द्वारा परीक्षण की सुविधा, बीमार पशुओं के लिए अलग व्यवस्था, फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेट्री, जलापूर्ति, ट्रीटमेंट प्लांट, सिवरेज— ड्रेनेज सिस्टम सहित जीरो-डिस्चार्ज सुनिश्चित की जाएगी।

(ग) प्रत्येक दिन 550 पशुओं के स्लॉटर हेतु 167 स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन किया गया है।

(घ) डी०पी०आर० में प्रतिदिन 350 बकरे व 200 भैंस के प्रसंस्करण का अनुमान है। इसमें 75 प्रतिशत स्वयं का उत्पादन व 25 प्रतिशत रथानीय कसाईयों को सेवा के रूप में उत्पादन शामिल है। स्वयं उत्पादन का निर्यात भी किया जा सकेगा।

(ङ) परियोजना वित्तीय रूप में सुदृढ़ (financially viable) है। परियोजना का रिटर्न (IRR) लगभग 25 प्रतिशत वार्षिक है जो वर्तमान बाजार दर पर काफी बेहतर है।

6. आधुनिक वधशाला निर्माण की इस परियोजना के कार्यान्वयन से न सिर्फ पटना में स्वारक्ष्यकारी (Hygienic) मीट उत्पादों की सुलभता होगी व सड़क किनारे पशुवध में कमी आएगी बल्कि राज्य में निजी निवेश के माध्यम से निर्यातोन्मुखी मीट प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

उपर्युक्त तथ्यों व प्रावधानों के आलोक में तथा बिहार राज्य में मीट प्रसंस्करण की असीम संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्पर्क विचारोपरान्त पटना में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा रु० 10.97 करोड़ ग्रांट के साथ स्थीकृत आधुनिक वधशाला (Abattoir) के जन-निजी भागीदारी अंतर्गत निर्माण पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की गई।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डा० एस० सिद्धार्थ,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 822-571+200-डी०पी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>